भारत का चीनी उत्पादन पहुंचेगा उच्च स्तर पर

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 1 मई

भारत का चीनी उत्पादन इस बार सभी उम्मीदों को मात देता नजर आ रहा है। सभी पूर्वानुमानों को पछाड़ते हुए चीनी उत्पादन 2.8 करोड़ टन के स्तर तक पहुंच सकता है। जबरदस्त गन्ना उत्पादन और पेराई का समय बढ़ाने की वजह से चीनी उत्पादन काफी उच्च स्तरों तक पहुंच सकता है। इससे पहले वर्ष 2006-07 में भारत में 2.836 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

अभी भी करीब 25 फीसदी चीनी मिलों में गन्ने की पेराई का काम जारी है जिसकी वजह से अप्रैल के आखिर तक 2.737 करोड़ टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान है। कुल 532 चालू मिलों में से 130 में परिचालन अभी भी जारी है क्योंकि ये चीनी मिलें जहां स्थित हैं वहां गन्ने की उपलब्धता काफी अधिक है। कई मिलें पहले ही बंदी की घोषणा कर चुकी हैं क्योंकि फिलहाल वहां गन्ना उपलब्ध नहीं है। इस साल चीनी का उत्पादन पिछले साल के 2.44 करोड़ टन उत्पादन के मुकाबले 34.3 लाख टन अधिक होगा। गन्ने का बकाया 21,000 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच चुका है। हालांकि अतिरिक्त उत्पादन के साथ ही बकाया और भी बढ़ सकता है। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा, '130 चीनी मिलें अभी भी काम कर रही हैं और तमिलनाडु में सीजन से पहले होने वाली पेराई को ध्यान में रखते हुए कुल चीनी उत्पादन 2.8 करोड़ टन के स्तर तक पहुंच सकता है। हालांकि वर्ष 2006-07 का रिकॉर्ड टूटना मुश्किल है।'

चीनी उत्पादन (करोड़ टन में)

पेराई वर्ष	(अक्टू-सितंबर)
2014-15*	2.80
2013-14	2.44
2012-13	2.514
2011-12	2.634
2010-11	2.439
2009-10	1.891
2008-09	1.44
2007-08	2.63
2006-07	2.836

स्रोतः इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, *अनुमान

इस बीच चीनी मिलें गन्ना किसानों के बढ़ते बकाये को लेकर चिंतित हैं क्योंकि बकाया रकम का भुगतान अगले सीजन की शुरुआत से पहले करना होता है। इसके अलावा सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। कच्चे चीनी पर आयात शुल्क को 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने के साथ ही एथेनॉल पर 12.36 फीसदी की छूट देने जैसे कदम उठाए हैं।

खाद्य मंत्रालय ने साफ किया कि कच्ची चीनी के आयातक को प्रसंस्कृत सफेद चीनी को फिर से छह महीने का निर्यात करना होगा। वे अपने निर्यात प्रतिबद्धताओं के लिए कोई कच्ची चीनी आयात नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एथेनॉल पर 12.36 फीसदी की छूट से मिलों को तेल विपणन कंपनियों को बेचने पर 5 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त मिलेंगे। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक सरकार को कम से कम 50 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार करना होगा और इससे उद्योग में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और किसानों के बकाये का भुगतान करने में मदद मिलेगी। वरना अगले सीजन में चीनी मिलों के लिए पेराई जारी रखना मुश्किल हो जाएगा।

Business Standard
2/5/15